

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3245
12.07.2019 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण

3245. श्री गौतम गंभीर:
श्री जगदम्बिका पाल:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विभिन्न सर्वेक्षणों ने विश्व में 20 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 14 शहरों को रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा करने हेतु हितधारकों के साथ बैठक की है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें भाग लेने वाले राज्यों/अधिकारियों के क्या नाम हैं और इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई है और इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (घ) दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गत तीन वर्षों में की गई बैठकों का ब्यौरा क्या है और इसकी रिपोर्ट क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और
- (ङ.) बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत उपायों और उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उक्त नीतिगत उपायों के कार्यान्वयन के लिए कितना समय लगने का अनुमान है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) वर्ष 2016-2018 के दौरान महानगरों/दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समूहों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़ा **अनुबंध** में दिया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2016-18 के दौरान सभी 50 शहरों में SO₂ के स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) के अंदर थे। NO₂ के संबंध में 17 शहरों में बढ़ता हुआ रूझान दिखाई पड़ा, 16 शहरों में घटता हुआ सांद्रण दिखाई पड़ा, 16 शहरों में घटता-बढ़ता रूझान दिखाई दिया और 1 शहर में स्थिर सांद्रण का पता चला। PM₁₀ के संबंध में 14 शहरों में बढ़ता हुआ रूझान दिखाई दिया है, 14 शहरों में घटता हुआ सांद्रण दिखाई पड़ा है, 22 शहरों में घटता-बढ़ता हुआ रूझान दिखाई पड़ा है। PM_{2.5} के संबंध में 17 शहरों के लिए रूझान उपलब्ध है और 17 शहरों में से, 08 शहरों में बढ़ता हुआ रूझान 04 शहरों में घटता हुआ सांद्रण और 05 शहरों में घटता-बढ़ता हुआ रूझान दिखाई दिया है।

(ख) से (घ) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें दिल्ली और एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्री उपस्थित थे। साथ ही दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्य बल (एचएलटीएफ) का गठन किया गया है। सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भी इस मुद्दे के समाधान के लिए पड़ोसी राज्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई हैं।

(ङ.) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए अनेक विनियामक उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजनाएं

- (i) दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, उसके नियंत्रण एवं उपशमन के लिए 12 जनवरी, 2017 को श्रेणीकृत अनुक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) अधिसूचित की गई। इसके तहत, चार वायु गुणवत्ता सूचकांको

(एक्यूआई) नामतः मध्यम से खराब, बहुत खराब, गंभीर और गंभीर से भी अधिक अथवा आपातकाल की स्थिति से निपटने हेतु श्रेणीकृत उपायों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को अभिज्ञात किया जाता है।

- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2018 में एक व्यापक कार्य योजना (सीएपी) अधिसूचित की गई है, जिसमें दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, उसके नियंत्रण एवं उपशमन के लिए अभिज्ञात कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु समय-सीमाओं एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को अभिज्ञात किया गया है।

अन्य शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजनाएं

- (i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक PM_{10} और $PM_{2.5}$ के सांद्रण में 20 से 30% की कमी लाने के लक्ष्य से वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक ढंग से निपटना है। इसमें सांद्रण की तुलना के लिए वर्ष 2017 को आधार वर्ष के रूप में रखा गया है। इस कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य देश भर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन हेतु व्यापक प्रबंधन योजना सुनिश्चित करने के अलावा परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को प्रभावकारी ढंग से बढ़ाना और विकसित करना तथा जन-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के उपायों में वृद्धि करना है।
- (ii) वर्ष 2011-2015 की अवधि के लिए प्राप्त परिवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों और डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट 2014/2018 के आधार पर 102 ऐसे शहरों को अभिज्ञात किया गया है जहां वायु की गुणवत्ता परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है। जमीनी तौर पर कार्यान्वयन के लिए कुल 86 शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा देश भर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, उसके नियंत्रण और उपशमन के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

निगरानी

- परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना। वर्तमान में, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के तहत पूरे देश में 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में 339 शहरों को शामिल करते हुए 779 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 102 शहरों में 170 स्थानों पर तात्कालिक (रीयल टाइम) निगरानी की जा रही है।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से अक्टूबर, 2018 में दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता शीघ्र चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन।

परिवहन

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के अन्य भागों में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानक अपनाना।
- स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन जैसे गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि), इथेनॉल मिश्रण की शुरुआत करना।
- सड़कों पर वाहनों की अधिकता के कारण भीड़-भाड़ को कम करने हेतु सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और सड़कों में सुधार तथा और ज्यादा पुलों का निर्माण।
- दिल्ली से अ-लक्षित वाहनों के मार्ग को डाइवर्ट करने हेतु पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे और पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रचालन।
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करने को व्यवस्थित बनाना।
- दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता के इंजन वाले डीजल वाहनों पर पर्यावरण संरक्षण प्रभार (ईपीसी) लगाया गया है।

उद्योग

- 15 अक्टूबर, 2018 से बदरपुर ताप विद्युत परियोजना को बंद कर दिया गया है।
- विद्युत संयंत्रों के लिए और कठोर उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना।
- दिल्ली और एनसीआर में सभी ईट-भट्टों को मिश्रित प्रौद्योगिकी अपनाने का निदेश दिया गया है।

- दिल्ली और एनसीआर में रेड श्रेणी के सभी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समय-समय पर उत्सर्जन मानको का संशोधन।
- पेट कोक और भट्टी तेल पर प्रतिबंध- दिल्ली और एनसीआर राज्यों में चूना भट्टियों/सीमेंट भट्टियों और कैल्शियम कार्बाइड उद्योग में पेट कोक के प्रयोग की निगरानी।

बायोमास और ठोस अपशिष्ट

- वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू की गई है।
- बायोमास/कचरा के जलाने पर प्रतिबंध लगाना।
- दिल्ली में इस समय 5100 टन प्रतिदिन (टीपीडी) की कुल क्षमता वाले 3 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले (डब्ल्यू-टी-ई) संयंत्र प्रचालित हैं।
- वर्ष 2016 में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्टों को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं।

धूल-कण

- निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
- दिल्ली में मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है और वर्तमान में सड़कों की सफाई के लिए 60 मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

जन-संपर्क अभियान

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार ने 10-23 फरवरी, 2018 के दौरान दिल्ली के लिए स्वच्छ वायु अभियान की शुरुआत की थी और दिवाली से पहले और उसके बाद 1 नवंबर, 2018 से 10 नवंबर, 2018 के दौरान वायु प्रदूषण फैलाने वाले कार्यकलापों को नियंत्रित करने हेतु "स्वच्छ वायु अभियान" नामक एक विशेष अभियान आरंभ किया था।
- मंत्रालय द्वारा हरित अच्छे कार्यों, जिनमें साईकिल की सवारी करने को बढ़ावा देने, जल और बिजली बचाने, पेड़ लगाने, वाहनों का उचित अनुरक्षण करने, सड़कों पर लेन अनुशासन का पालन करने तथा कार पूलिंग द्वारा सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण हेतु लोगों की भागीदारी और नागरिकों में जागरूकता सृजन अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जन-शिकायतों के समाधान हेतु 'समीर ऐप', ई-मेल (aircomplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्क' (फेसबुक और ट्विटर) आदि के माध्यम से एक तंत्र विकसित किया गया है।

दिल्ली में उठाए गए इन कदमों के फलस्वरूप, वर्ष 2018 में 'अच्छे', 'संतोषजनक' और 'सामान्य', दिनों की संख्या बढ़कर 159 हुई है जबकि वर्ष 2017 में यह 152 थी और वर्ष 2016 में 106 थी और 'खराब', 'बहुत खराब', और 'गंभीर', दिनों की संख्या जो 2017 में 213 थी और 2016 में 246 थी वह 2018 में घटकर 206 हो गई थी वर्ष 2016-2018 के दौरान सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों (सीएएक्यूएमएस) के तहत प्राप्त किए गए दिल्ली के परिवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2018 में PM_{2.5} के स्तरों में वर्ष 2017 की तुलना में 7.3% और वर्ष 2016 की तुलना में 14.8% की कमी हुई और वर्ष 2018 में PM₁₀ के स्तरों में वर्ष 2017 की तुलना में 8.6% और 2016 की तुलना में 16.5% की कमी हुई है।

वायु प्रदूषण के संबंध में श्री गौतम गंभीर और श्री जगदम्बिका पाल द्वारा दिनांक 12.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3245 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध

एनएएमपी (मैनुअल) के तहत 2016, 2017 और 2018 के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले/शहरी समूहों वाले शहरों की वायु गुणवत्ता की स्थिति ($\mu\text{g}/\text{m}^3$ में वार्षिक औसत)

क्र. सं.	राज्य	क्र. सं.	शहर	2016				2017				2018			
				SO ₂	N O ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	SO ₂	N O ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}
1.	आंध्र प्रदेश	1.	विजयवाड़ा	6	44	102	-	6	29	99	-	5	21	77	29
		2.	विशाखापट्टनम	8	18	77	-	9	17	73	-	10	20	77	49
2.	बिहार	3.	पटना	4	32	212	-	5	39	156	-	5	51	207	
3.	चंडीगढ़	4.	चंडीगढ़	2	21	105	12 3	2	16	109	64	2	17	102	50
4.	छत्तीसगढ़	5.	दुर्ग-भिलाईनगर	9	23	108	-	8	21	97	-	8	19	84	-
		6.	रायपुर	12	31	148		10	27	103		14	20	65	
5.	दिल्ली	7.	दिल्ली	7	66	278	11 8	7	68	241	106	6	73	223	121
6.	गुजरात	8.	अहमदाबाद	14	27	108	34	14	29	120	38	16	29	236	73
		9.	राजकोट	13	21	92	32	16	22	106	37	19	23	203	64
		10.	सूरत	13	22	92	31	16	26	106	36	22	29	176	57
		11.	वडोदरा	14	23	92	30	16	23	108	36	20	25	188	60
7.	हरियाणा	12.	फरीदाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	जम्मू और कश्मीर	13.	श्रीनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-
9.	झारखंड	14.	धनबाद	15	37	226	-	15	37	238	-	14	37	264	-
		15.	जमशेदपुर	36	45	136	-	36	45	131	-	37	46	128	-
		16.	रांची	20	37	196	-	19	37	142	-	18	36	122	-
10.	कर्नाटक	17.	बैंगलोर	3	31	103	51	2	31	92	46	2	30	90	47

11.	केरल	18.	कोच्चि	2	20	48	-	2	19	51	-	3	16	57	-
		19.	कोल्लम	4	8	46	-	3	6	43	-	3	5	47	-
		20.	कोझिकोड	2	18	51	-	2	18	47	-	2	10	54	6
		21.	मलप्पुरम	2	17	37	-	2	21	32	-	2	26	31	-
		22.	तिरुवनंतपुरम	10	25	53	-	10	26	49	-	9	24	49	-
		23.	तिथूर	2	5	54	-	2	5	56	-	3	9	41	-
12.	मध्य प्रदेश	24.	भोपाल	3	15	89	27	4	15	93	41	7	14	135	59
		25.	ग्वालियर	10	14	96	52	10	17	110	47	13	21	134	62
		26.	इंदौर	11	20	95	54	11	21	80	43	10	19	88	41
		27.	जबलपुर	10	23	71	32	10	21	74	23	7	17	119	43
13.	महाराष्ट्र	28.	औरंगाबाद	14	39	92	-	10	33	83	-	13	35	70	-
		29.	मुंबई	6	30	119	-	3	18	151	40	2	21	166	46
		30.	नागपुर	16	26	118	-	9	27	102	-	10	28	103	44
		31.	नासिक	13	27	85	-	12	22	81	-	12	21	85	-
		32.	पुणे	28	78	107	-	21	65	102	-	37	75	106	-
		33.	थाणे	18	60	122	-	18	47	125	-	17	44	108	-
		34.	वसई - विरार	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14.	पंजाब	35.	अमृतसर	12	29	194	-	11	27	168	-	13	34	177	-
		36.	लुधियाना	11	25	139	-	10	28	162	-	9	32	162	-
15.	राजस्थान	37.	जयपुर	8	33	199	-	8	30	177	-	8	32	165	-
		38.	जोधपुर	6	23	168	-	6	21	180	-	7	24	223	-

		39.	कोटा	7	30	109	-	8	28	130	-	7	28	152	-
16.	तमिलनाडु	40.	चेन्नई	10	18	65	25	9	17	62	32	9	16	78	34
		41.	कोयंबटूर	6	24	59	35	5	26	49	34	6	23	54	32
		42.	मदुरै	15	24	76	38	14	23	67	30	12	20	84	34
		43.	त्रिची	12	20	95	27	12	20	86		17	23	110	53
17.	तेलंगाना	44.	हैदराबाद	5	27	101	49	6	28	108	54	5	30	105	55
18.	उत्तर प्रदेश	45.	आगरा	5	22	198	-	4	19	185	124	4	22	209	106
		46.	इलाहाबाद	4	37	196	-	4	40	140	-	4	45	231	-
		47.	गाज़ियाबाद	15	28	235	-	22	34	280	-	21	43	245	103
		48.	कानपुर	7	39	217	-	7	45	224	-	7	47	218	-
		49.	लखनऊ	8	27	214	-	8	26	246	102	7	30	217	108
		50.	मेरठ	7	55	157	-	7	52	153	-	7	58	177	-
19.	पश्चिम बंगाल	51.	वाराणसी	11	32	256	-	10	38	244	-	9	34	189	-
		52.	आसनसोल	13	42	211	88	12	37	163	67	13	35	146	58
		53.	कोलकाता	4	49	113	70	6	41	120	71	6	44	148	86

ध्यान दे: NA- शहर में कोई निगरानी स्टेशन नहीं है, '-' डेटा उपलब्ध नहीं है, आवासीय, औद्योगिक, ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) $SO_2 = 50 \mu g / m^3$, $NO_2 = 40 \mu g / m^3$, $PM_{10} = 60 \mu g / m^3$ और $PM_{2.5} = 40 \mu g / m^3$ और $SO_2 = 20 \mu g / m^3$, $NO_2 = 30 \mu g / m^3$, $PM_{10} = 60 \mu g / m^3$ और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के लिए $PM_{2.5} = 40 \mu g / m^3$ / वर्ष 2018 के लिए तालिका में प्रस्तुत डेटा आज की तिथि के अनुसार उपलब्ध है।
